[Shri Lal K. Advani.]

the Government is ready to consider the entire gamut of foreign policy in this House. It was mentioned in that context that on the occasion, it might be only on external affairs. The Prime Minister has indicated that he would also participate in that debate.

MR. CHAIRMAN: Now, Calling Attention. Shri Kalp Nath Rai.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Pitiable Condition of Sugarcane growers in the Country

SHRI KALP NATH RAI (Uttar Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Agriculture and Irrigation to the pitiable condition of sugarcane growers in the country due to sugar policy of Government and non-payment of the price of sugarcane to growers by the sugar mills particularly in U.P., Bihar and Haryana, during the current crushing season causing hardships to them.

[**Mr. Deputy Chairman** in the Chair]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): Sir, the motion concerns a subject which has figured on a number of occasions in this august House, *viz.*, Sugarcane and sugar economy of the country and the welfare of the sugarcane growers which is upper most in the minds of the Government. It is not necessary, I hope, for me to reiterate that many of the measures Government had already implemented during the current year relating to sugarcane and sugar and, for that matter of other sweetening agents from sugarcane *viz.*, gur and khandsari, have primarily been oriented to improve the lot of the sugarcane growers. In saying this I should not be misunderstood as being unaware or oblivious of the genuine grievances of the sugarcane growers during the current season. But we should ponder as to why this has happened. Sir, if I may say with all seriousness the present state of over abundant supply of cane has been a legacy of the past.

I may now briefly set out the position of sugar and sugarcane production and utilisation during the season and the various policy measures the Government have adopted. The sugar production has been increasing during the last five years. From a level of 39.48 lakh tonnes during 1973-74 it is estimated that the production figure for 1977-78 will be 65 lakh tonnes, thus, surpassing the previous year's production of 48.43 lakh tonnes by 34 per cent. The record production is due to the bumper sugarcane crop during 1977-78 which is estimated at 172 million tonnes as against 154 million tonnes last year. In this context, the sugar industry's performance to absorb this excess production has been very satisfactory and is likely to account for 19 million tonnes more of sugarcane this year. However, in spite of this, imbalances have been noticed in the sugarcane economy as the alternative sweetening agents, namely, gur and khandsari have drawn lesser amounts of sugarcane this year. At the beginning of the season and a little later in March, the Govt. had announced a series of measures regarding sugar, gur and khandsari. It may be recalled that excise duty concession, increase in levy price for sugar, decision to export sugar to the full extent of our international quota, reduction in bank margin for credit to gur and khandsari, removal of restrictions on export of gur and khandsari and market purchase of gur by public sector agencies like NAFED and FCI, have been the more important measures undertaken to stabilise the sugarcane and sugar economy. As stated earlier if in spite of these measures a situation of excess availability of sugarcane still

persists, it is primarily due to the lesser offtake of cane by gur and khandsari industries. Problems have arisen also regarding the huge stocks of sugar. The stocks at present are of the order of 45 lakh tonnes. In spite of increasing the domestic consumption by 23 per cent the present level of stocks have resulted out of the record production which in turn was the result of the incentive excise rebate for late crushing.

As a result of this single measure of excise duty rebate I am very happy to announce that the production of sugar during the off season, that is after April will be over 12 lakh tonnes as against the average of a little over 2 lakh tonnes in earlier years. This alone would result in an extra offtake of cane of the order of 12.5 million tonnes which is a record unparalleled in the last 30 years.

Turning specifically to the States of Uttar Pradesh, Bihar and Haryana mentioned in the Calling Attention notice let me set out some of the principal features. The factories in these States respectively had crushed 201, 31 and 16 lakh tonnes of cane during this season as against 151, 21.5 and 12 lakh tonnes respectively in the entire season last year. Still there are 39 factories in Uttar Pradesh continuing the crushing as against nil at this time last year. All bonded cane has also already been crushed.

The record drawal of extra cane and off season crushing, and present level of stocks have, however, led to a situation affecting the liquidity of resources of the industry with consequent impact on cane arrears. Even so, I wish to emphasise that a number of measures have been taken by the Government to correct the situation. The Reserve Bank of India have informed that, at our instance, extra credit provided to the joint stock sector of the industry alone has been roughly about Rs. 100 crores as compared to the last year. The Sugarcane (Control) Order has also been amended in February 1978 to ensure a payment of 15 per cent interest on balance cane payments beyond the statutory period of 14 days. We are also exploring further measures to impart liquidity to the financial position and thereby enable the sugar industry to discharge its obligations primarily in clearing the cane arrears.

I can assure the House that the Government is fully alive to the problems faced by the cane growers and it is committed to take all possible measures to help them. Government will continue to watch the situation and take such further measures as are considered appropriate I am confident that in a reasonable period the liquidation of cane arrears would be satisfactorily under control.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, आज जब मैं पूरे देश के अन्दर आज की चीनी सम्बन्धी नीति पर कुछ बातें कहना चाहता हूं तो मैं इस सदन के अन्दर देश के हर कोने-कोने से आए हुए और हर पार्टी के साथियों से भी अपील करना चाहूंगा कि वे इस सरकार की गन्ना नीति और चीनी नीति के सम्बन्ध में विचार करें। क्या कभी हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा देखा गया कि गन्ना जो दिसम्बर और जनवरी महीने तक या फरवरी महीने तक ही पेरा जाना चाहिए था वह गन्ना आज जुलाई के महीने में भी लाखों एकड़ जमीन में खडा है।

आदरणीय उपसभापति महोदय, इस देश का किसान गन्ना बोता है, गन्ना बोने के बाद गन्ने की कटाई करता है, दूसरी फसल उसमें गेहूं की बोता है, गेहूं की फसल काटने के बाद तीसरी फसल उसमें धान की बोता है और 3 फसलों का लाभ वह उठाता है, और अपना ही लाभ नहीं उठाता है, इस देश के करोड़ों की जनता को वह अन्न भी देता है। लेकिन उपसभापति महोदय, सरकार की

[श्री कल्पनाथ राय]

नीति के कारण किसान जो गन्ना काट कर गेहूं बोना चाहिये, वह गेहूं भी नहीं बो पाया और गेहूं को काट कर धान बोना चाहिए, पैडी बोनी चाहिए, लेकिन आज वह पैडी से भी वंचित हो गया है इस सरकार की नीति के कारण। आदरणीय उपसभापति महोदय, हमारे कृषि मन्त्री महोदय किसानों के काज में इण्टरेस्टेड हैं, मैं जनता हूं किसानों के सवाल पर उन्होंने हमेशा लड़ाई लडी हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जनता पार्टी की हुकूमत जब इस देश में आई, ग्रामीण विकास के नाम पर और किसानों के नाम पर, तो लोगों के दिलों में एक आशा का चिराग जला था और देश के ग्रामीण अंचल में एक विश्वास का अंकुर प्रस्फुटित हुआ था, कि कांग्रेस की सरकार तो गई और अब हमारे किसानों की, ग्रामीणों की, हमारे गांव वालों की सरकार आई है, परन्तु आज पिछले 15 महीनों से जितनी खराब हालत आज गांवों के किसानों की है--मैं आदरणीय भानू प्रताप जी से कहना चाहता हूं--उतनी हालत खराब इसके पहले कभी नहीं थी। आज गन्ने के किसानों पर दसगुना लगान बढ़ गया। 15 महीनों के अंदर आठ गुना, 6 गुना और दस गुना लगान बढ़ गया। उस की बिजली के रेट जो 12 रुपया प्रति हार्स पावर थे वह बढ़ कर 15 रुपए हो गये। उस के घर की बिजली के रेट बढ़ गये। किसानों के ट्रेक्टर के दाम बढ़ गये। उस के लिये सीमेंट के दाम बढ़ गये, डीजिल के दाम बढ़ गये, ईंट का दाम बढ़ गये। किसानों की जिन्दगी में इस्तेमाल होने वाली जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन सब चीजों के दाम एक एक कर के बढ़ गये और किसान जो गन्ना पैदा करता है, जो कपास पैदा करता है, जो जूट पैदा करता है, जो देश की सारी चीजों को पैदा करता है, जो तम्बाकू पैदा करता है, उन सारी चीजों के दाम घट गये और वह चीजें घटे हुए दामों पर बिकने लगीं।

माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि गन्ना हम तीन प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत गन्ना गुड़ बनाने के काम मे आता है। 20 प्रतिशत गन्ना खांडसारी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और 40 प्रतिशत गन्ना चीनी बनाने के काम में आता है। आप कहते है कि हमारे देश में ज्यादा उत्पादन हो गया इस लिए हम किसानों के हितों की रक्षा नही कर सके। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी नही है कि इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड आफ पर कैपिटा कंजम्पशन जो है शूगर का उसमें हिन्दुस्तान का स्थान अन्तिम है। इस मुल्क में चीनी या गन्ने का उत्पादन ज्यादा कैसे होगा। तो आखिर कारण क्या है। खुद कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि गन्ने की पेराई अक्तूबर के महीने में, सितम्बर के महीने में सरकारी आदेश के अन्तर्गत शुरू हो जानी चाहिये और चीनी मिल मालिकों को आदेश दिया जाना चाहिये कि तुमको फरवरी तक किसानों का गन्ना लेना होगा वरना तुम लोग सरकार की जेलों में बन्द होंगे। मैं जानता हूं कि किसी मिल मालिक की हिम्मत नहीं है कि सरकार की पोलिटिकल विल पावर का वह उल्लंघन कर सके। ऐसा कोई मिल मालिक या कोई पूंजीपति इस देश का नही कर पायेगा, लेकिन उपसभापति महोदय, सितम्बर में गन्ने की पेराई नही शुरू हुई, अक्तूबर में वह नहीं शुरू हुई, नवम्बर में वह नहीं शुरू हुई, वह दिसम्बर के महीने में शुरू हुई और ऐसा क्यों हुआ। अगर गन्ना अक्तूबर में पेरा जाना शुरू हो गया होता तो उसमें से रस कम निकलेगा और यदि नवम्बर में उसकी पेराई शुरू होंगी, दिसम्बर, में शुरू होगी तो उसमें से ज्यादा रस निकलेगा। तो पिछली सरकार यह करती थी कि तुम अक्तूबर से गन्ने की पेराई शुरू करो और इसके लिए हम उसको इंसेंटिव देते थे। वह मिल मालिक उस समय पेराई शुरू कर देता था और फरवरी तक सारे देश का गन्ना पेर लेता था और फरवरी में लाखों हैक्टयर जमीन में गन्ने को काट कर गेहूं

की फसल बो दी जाती थी जिसके कारण यहां इतना गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था और उसके साथ ही हमको गन्ना भी मिलता था । लेकिन चूंकि इस सरकार पर चीनी मिल मालिकों का मोदी आदि का प्रभाव है---मैं यह आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि कृषि मंत्री महोदय भी इस स्थिति को सम्हाल नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे बड़ी ताकतें है। किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि "This Janata Government is a prisoner in the hands of the capitalists and the multinationals. Therefore, I have resigned from this Government and I feel relieved." इस देश के किसानों के नेता ने यह बात कही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिर इतनी देर से गन्ने की पेराई क्यों शुरू हुई । मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश के किसानों का कितने लाख या कितने करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों पर बाकी है और कितना रुपया किसानों को दे दिया गया है । अभी भानु प्रताप सिंह जी ने कहा है कि किसानों के बकाया रुपये पर 3 प्रतिशत सूद उनको दिया जायेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसान बैंक से कर्ज लेगा तो उसको 16 प्रतिशत के हिसाब से या 12 प्रतिशत के हिसाब से सूद देना पड़ेगा और चीनी मिल मालिक जब उसको उसका पैसा दो साल बाद पेमेंट करेगा तो वह उसको 3 प्रतिशत सूद देगा यह कौन सा न्याय है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने तीन नही कहा, मैंने 15 प्रतिशत कहा है ।

श्री कल्पनाथ राय : थैंक यू, वैरी मच ।

आदरणीय उपसभापति महोदय, मेरा कहना है कि देवरिया जिले के अन्दर 14 मिलें हैं । हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत से संसद् सदस्य यहां मौजूद हैं । चीनी मिलों के मालिकों ने अपने चीनी के कारखानों से इतना लाभ उठाया है कि इनके सारे हैड-आफिस कलकत्ता, बम्बई में हैं और चीनी मिल मालिकों ने चीनी की एक मिल से इतना पैसा कमाया कि 10 कपड़े की मिलें बनाई, स्टील की मिलें बना ली । चीनी की एक मिल शुरू करके और बहुत से कारखाने स्थापित करके करोड़ों अरबों रुपया किसानों के गन्ने पर कमाया और उनके गले पर छुरी चलाई ।

आज गुड़ के दाम 24 रुपया क्विंटल बाजार में बिक रहा । 20 रुपया क्विंटल खोइया, 12 रुपया क्विंटल गुड़ बिक रहा है और 4 रुपए क्विंटल भी आज मुजफ्फरनगर में किसानों के खेतों में गन्ना जो खड़ा है उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है । हमने किसानों से पूछा कि इसको काटकर धान क्यों नहीं बोते हो । तो उन्होंने कहा कि इसको काटकर गाड़ी पर लादने में जितना पैसा खर्चा होगा मिलों मे उतना भी पैसा हमको नहीं मिलेगा । इसलिए हम उसको जला रहे है। यह है हमारी सरकार की नीति । क्या कारण है कि आज हिन्दुस्तान के किसान जो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में गन्ने का उत्पादन करते है आज भुखमरी के शिकार बने हैं ? उसका कारण यह है कि हमारी पिछली सरकार हमेशा 6 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया करती थी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जब चीनी की मांग होती थी तो हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपयुक्त समय पर अपने देश की चीनी को भेजते थे । इसके परिणामस्वरूप जो देश चीनी खरीदने वाले हैं वह हमारे गुड़ व चीनी को खरीद लेते थे और हमारे देश से 6 लाख टन शूगर बाहर जाती थी ; उसका जो मार्केट के अन्दर फलक्चयुएशन होता था उसके कारण कम्पीटीशन में देश के किसानों को उसके गुड़, चीनी और खांडसारी का उचित दाम मिल जाया करता था । लेकिन वर्तमान सरकार की बैंकरप्ट पालिसी के कारण जब दुनियां के बाजार में चीनी खरीदने वाले मुल्कों को हिन्दुस्तान से

[श्री कल्पनाथ राय]

चीनी चाहिये थी तो हमने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। जब हायतोबा मच गई और जब अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों ने दूसरे देशों से खरीद लिया तब इन्होने कहा कि हम एक्सपोर्ट अलाउ करते है। दुनियां के खरीदने वाले देशों ने जितनी उनको जरूरत थी उनको कहा कि हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया और जब उन्होने दूसरे देशों से खरीद लिया और जब हमारी चीनी बाजार में मिट्टी के दाम बिकने लगी तो कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि एक्सपोर्ट करो। जब एक्सपोर्ट शुरू किया तो दुनियां में खरीदने वाला नहीं है। परिणाम-स्वरूप हमारी चीनी नही बिकी। The bankrupt policy of this Government is responsible for the total destruction of kisans in this country.

आदरणीय उपसभापति महोदय, जो मंत्री महोदय ने पाइंट्स कहे हैं, कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। आप भी किसान परिवार से आते है, मैं कोई ऐसी बात नही कह रहा हूं जिससे कि आपको कोई तकलीफ हो। 102 लाइसेंस ज्वाइंट सेक्टर में और कोआपरेटिव सैक्टर में पिछली सरकार ने जारी किये। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हुं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि सौ करोड़ रुपया हमने दिया है तो 102 लाइसेंसो में कितने इम्प्लीमेंट हुये, कितने इम्प्लीमेंट नहीं हुये। कितने ज्वाइंट सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर मे मिले लगाने के प्लान सरकार के पास है? और कब तक यह हो जाएगा इसकी घोषणा इनको करनी चाहिये।

दूसरी बात मैं दाम नीति के बारे में कहना चाहता हूं। जनता सरकार में बैठने वाले जितने मंत्री लोग हैं उन सब लोगों ने, विशेषकर समाजवादी नेताओं ने पूंजीपतियों के खिलाफ भाषण दिये थे और यह कहते थे कि यदि हम हुकूमत में आए तो हम 25 रुपए क्विंटल, 20 रुपए क्विंटल से कम गन्ने का दाम नहीं रखेंगे। मधु लिमये, जार्ज फर्नान्डीज आदि बहुत से सदस्य समाजवाद की दिन रात बात करते थे, समाजवाद की बात करते-करते इन के बाल पक गये हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के किसानों की बात करते रहे हैं किन्तु बदकिस्मती है इस देश की कि आज वह कुछ नहीं कर रहे है। किसान के नेता चौधरी चरण सिंह जिसकी सारी राजनीति ही शूगर पर मुनहसिर करती थी आज वह भी पीछे है? आपको याद होगा कि सन् 67 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे और उसी वक्त किसानों को 13–14 रुपए गन्ने के दाम मिले थे। उस समय चौधरी चरण सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सोने और चांदी से तोला था और कहा था कि चौधरी साहब का राज आया है और गन्ने का दाम 14 रुपए मिला है। मेरठ और दूसरे शहरों की सभाओं में पहली बार यह कहा गया कि किसान के बेटे को मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला और गन्ने का दाम 14 रुपए मिला। क्योंकि चन्द्रभानु गुप्त पूंजीपतियों के हिमायती थे इसलिए किसानों को गन्ने का सही दाम नहीं मिला। उपसभापति जी, आपको मालूम है किसानों को रुपया कैसे मिला? किसानों को रुपया मिला था 67 में और वह इसलिए कि श्रीमती इन्दिरागांधी, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने हिन्दुस्तान की चीनी का एक्सपोर्ट विदेशों में किया था और इससे 500 करोड़ रुपए फारेन एक्सचेंज हमने कमाये। इसी के कारण उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ हुआ। मै बताना चाहता हूं कि किसान इस

बात को समझता नहीं । किसान एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, सोशलिज्म, गांधीवाद आदि चीजों को जानता नहीं ।

चौधरी चरण सिंह को देश की नेतागिरी आ गई और अब वह पूरे भारत के नेता बन गये और यहां तक कि मैंने मोरारजी देसाई को प्रधान मंत्री बनाया, इस हैसियत में आ गये । अब बोलो बेटा, चरण सिंह की जय, गन्ना बिके पौने छः ।

श्री उपसभापति : जरा संक्षेप में बोलिये बहुत समय ले रहे है ।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति जी, किसानों ने चौधरी चरण सिंह को सोने और चांदी से तोला था और आज वही किसान उन्हें मिट्टी से भी तोलने को तैयार नही है ।

दूसरी बात हमें कहनी है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के बारे में । एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना हुआ है किस लिए ? यह बना हुआ है किसानो के खेतो में पैदा की हुई चीजों के दाम तय करने के लिये । एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने इसका स्टेट्यूटरी दाम तय किया था 8 रुपए 50 पैसे। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और पूजी-पतियों के बीच गन्ने का दाम तय कराने का काम करता है । इट इज ए कोआर्डिनेटिंग बोडी । इस साल गन्ने का दाम तय हुआ 13 रुपए क्विंटल पूर्वी उत्तर प्रदेश मे और 14 रुपए क्विंटल पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे तो क्या कारण है कि आपकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा नही कर रही है ? यदि आप वास्तव में पूजीपतियों की रक्षा नही कर रहे है तो आपने कितने पूजीपतियों को जेलों में बन्द किया ।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य ने बहुत समय ले लिया है । संक्षेप में बोलिये।

श्री कल्पनाथ राय : मैं अपने सारे पोइंट तो कह लू ।

श्री उपसभापति : लेकिन कुछ समय की सीमा भी तो इसमें होनी चाहिये । हर रोज इस तरह से नही चलना चाहिये ।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है . . .

श्री उपसभापति : आप ऐसी बात तो घंटे भर नहीं कहेंगे । लेकिन दूसरे सदस्य भी हैं जिन्होंने बोलना है कृपया उनका भी ध्यान रखिये । अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा ।

श्री कल्पनाथ राय : मुझे आखिरी बात कहनी है कि अगर किसानों के हितो की रक्षा करनी है तो सरकार आज घोषणा करे । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब है कि अगले साल के लिए सरकार की दाम नीति क्या होगी, यह पता लगे ।

मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में आपकी नीति क्या होगी ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आप चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कब तक करेंगे और कब आप किसानों के हितों की रक्षा कर पायेंगे । मैं यह बात क्यों कह रहा हूं ? मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि पंजाब में गन्ने का दाम कोआपरेटिव सेक्टर में 16 रुपए से ज्यादा मिला है । महाराष्ट्र में किसानों को 14 रुपए क्विंटल की दर से गन्ने का दाम मिला है क्योंकि महराष्ट्र में कोआपरेटिव सेक्टर में और जौइन्ट सेक्टर के अन्तर्गत मिलें चल रही हैं । आन्ध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में,

[श्री कल्पनाथ राय]

मास में जहां पर जौंइन्ट सेक्टर में और कोआपरेटिव सेक्टर में मिलें काम करती हैं वहां पर किसानों को 12 रुपये और 14 रुपये क्विंटल के भाव पर गन्ने का दाम मिला है । लेकिन दिल्ली से लेकर बिहार तक जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर चीनी मिल मालिकों के हाथ गन्ने का काम है उन क्षेत्रों में इस सरकार ने किसानों की अंतड़ियां निकाल दी हैं और चीनी मिल मालिक किसान का खून चूस रहे हैं । यह सरकार और इनके मुख्य मंत्री किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं . . . (*Interruptions*) इसलिए हमारी यह मांग है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

आदरणीय उप-सभापति महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है . . .

श्री उपसभापति : आप बहुत समय ले चुके हैं अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, मुझे आखिरी पाइन्ट यह कहना है कि पिछले 15 वर्षों मे चीनी मिल मालिकों को इतनी एक्साइज में रिलीफ नहीं दी गई जितनी इस साल जनता सरकार ने चीनी मिल मालिकों को दी है । चीनी मिल मालिकों को पहले 85 करोड़ का, फिर 15 करोड़ का और फिर 10 करोड़ रुपयों का रिलीफ दिया गया । इस प्रकार से कुल 110 करोड़ रुपयों का एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दिया गया है । इतना रिलीफ पहले कभी नहीं दिया गया था । इतनी बड़ी मात्रा में एक्साइज में रिलीफ देने के बाद किसानों को इस तरह से लूटा गया है कि पिछले 30 वर्षों में कभी ऐसा नही हुआ । ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि इस देश के 10 करोड़ गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा हो सके ।

श्री भानुप्रताप सिंह : उपसभापति महोदय, माननीय श्री कल्पनाथ राय जी ने जितनी बातें कही हैं उनका सबका उत्तर देना तो कठिन है क्योंकि बहुत सी बातें जो उन्होंने कही हैं व वास्तविकताओं से इतनी दूर हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनका मूल समस्या से थोड़ा भी सम्बन्ध है या नहीं । उनका यह कहना कि सितम्बर में गन्ने की मिलें चल रही थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि सितम्बर में चीनी मिलें नहीं चलती हैं । उनका यह भी कहना कि फरवरी के महीने में चीनी मिलें बन्द हो गई थी । यह भी कभी नही होता । इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि फरवरी में गन्ना काटकर खेतों में गेहूं की बुआई होती है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में गेहूं की बुआई नहीं होती . . . . . (*Interruptions*)

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . (*Interruptions*)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, क्या इस तरह से आपस में सवाल जवाब होते रहेंगे ?

श्री उपसभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया सदन में शान्ति बनाये रखें ।

श्री भानु प्रताप सिंह : माननीय कल्पनाथ राय जी ने यह भी कहा कि पहले 10 मिलियन टन चीनी का एक्सपोर्ट होता था ।

श्री कल्पनाथ राय : 6 मिलियन टन, ... (*Interruptions*) मैंने 6 लाख कहा है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह भी गलत है । आपको 6 मियलयन और 6 लाख में क्या अन्तर है, यह भी पता नहीं है ।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे, तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी । मैंने कहा है—6 लाख टन । ये खुद खेती नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह की बात कह रहे हैं । यह मामला किसानों के हितों के सम्बन्ध में रखता है । इसलिए मंत्री महोदय को गम्भीरतापूर्वक हमारे सवालों का जवाब देना चाहिये ।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, अच्छा अब मैं उनकी बात मान लेता हूं । उनका जिक्र नही करूंगा क्योंकि करने लायक भी नही है । यह कहना कभी ऐसा नहीं हुआ है जब कि जुलाई तक मिलें चली हों, यह बात सही है । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कभी इस देश में न तो इतना गन्ना पैदा हुआ था और न इतनी चीनी । बावजूद इसके कि आप इसके लिए कुछ एप्रिसियेशन करें कि इतनी विकट परिस्थितियों में भी . . .

श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी (गुजरात) किसान संकट में है, एप्रिसियेशन क्या करें ।

श्री भानु प्रताप सिंह : आप सुनें तो समझ में आएगा । आपकी भी कोई जम्मेदारी है, देश की जो समस्याएं हैं उन से निपटने के लिए केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है । मैं चाहता हूं कि आप पहले सुनें और बाद में आप कुछ टिप्पणी करेंगे तो हम भी अवश्य ध्यान देंगे । अगर आप सुनें नहीं तो कोई नतीजा नहीं निकल सकता । मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ने के क्षेत्र मे हमारे दो सेक्टर हैं । एक तो आर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा अन-आर्गेनाईज्ड सेक्टर । आर्गेनाइज्ड सेक्टर मे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और मिलें आती है और अन आर्गेनाईज्ड सेक्टर में खांडसारी और गुड़ आते हैं । मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आर्गेनाईज्ड सेक्टर में जो काम किया है, उसके अनुसार किसानों को पेमेंट हुआ है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी वर्ष भी में जितने गन्ने की पेराई की गई उससे इस साल बहुत ज्यादा पेराई की गई है । इस साल 20 मिलियन टन ज्यादा पेरा गया है । पैदावार सिर्फ 18 मिलियन टन की बढ़ी है लेकिन फेक्टरियों ने 18 मिलियन टन के मुकाबले 19 लिमिलियन टन गन्ना अधिक पेरा है । तो इन फैक्टरियों ने इस मूसीबत को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है । अगर फेलियर हुआ है तो वह अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में हुआ है । आर्गेनाइज्ड सेक्टर ने किसानों की मदद करने, किसानो के लिए जो निर्धारित मूल्य था वह अदा करने मे कोई कसर नहीं रखी है । मूल्यों की बात कही जाती है । इसके पहले सीजन में आपकी हुकूमत थी । उससे ज्यादा किसानो को इस साल कीमत अदा की गई है । आपने एक्साइज ड्यूटी की चर्चा की । पिछले वर्ष के मुकाबले में चीनी की कीमत 80 रुपये क्विंटल गिरने के बावजूद भी किसानों को अगर ज्यादा कीमत मिली तो वह ऐसे ही संभव नही था जब तक उनको एक्साइज़ ड्यूटी में रिलोफ न देते । एक्साइज़ ड्यूटी रिलीफ इंडस्ट्री को मदद करने के लिए नही दिया गया बल्कि इसलिए दिया गया ताकि किसानों का अधिक गन्ना पेरा जा सके । बावजूद इसके पिछले साल की अपेक्षा 80 रुपये प्रति क्विंटल चीनी का दाम कम हो गया उसको देखते हुए भी उनको रिलीफ दिया गया । आप कहते हैं कि चीनी मिलों ने बहुत पैसा मुनाफा कमाया । मगर वह किसके राज मे कमाया ? आपने कहा जिसकी एक चीनी मिल थी उसके 10 कारखाने हो गये । मै यह पूछना चाहता हूं कि किसके राज में ऐसा हुआ ? क्या इसके लिए हम जिम्मेदार हैं ? हम आपसे यह कह सकते हैं । इक्का दुक्का मिलों को

[श्री भानु प्रताप सिंह]

नही जानता हूं सभी को देखा जाए तो शूगर इंडस्ट्री ने मुनाफा नही कमाया । यह केवल प्राइवट सेक्टर में नहीं है बल्कि कोआपरेटिव सेक्टर में भी है स्टेट सेक्टर में भी है। सब के आकड़े आप देखें कि क्या दुर्दशा इंडस्ट्री की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन को और किसानो को कुछ इसका एप्रिमियेशन करना चाहिए कि आज जुलाई में भी जब सचमुच चीनी बनाने का मौसम नहीं है फिर भी वे मिलें चला रहे हैं, हानि उठा कर चला रहे है लेकिन आप एसी बातें कहते है । फेलियर जो कुछ भी हुआ है वह गुड और खांडसारी सेक्शन मे हुआ है । श्रीमन्, मै यह बात कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार इस बात की जिम्मेदारी नही ले सकती कि किसान जितना भी पैदा करता है यानि अगर हमारा कोई नियंत्रण पैदावार पर नहीं है तो हम उनको ऊंची कीमत देते रह सकेगे, ऐसा कोई कमिटमेंट नही है और इस देश को तो छोड़िये, यह हुकूमत भी गरीब है, लोग भी गरीब है लेकिन अमेरिका जैसा देश भी जब किसानो को कीमतें देने का वादा करती है तब वह उसके एरिये पर नियंत्रण करता है । हर साल उनको बताया जाता है कि आप इससे ज्यादा गेहूं नही बो सकते है । इससे ज्यादा दूसरी फसलें नही बो सकते अब यहां भी यही समय आया है कि शायद हमको भी ऐसा करना पड़ेगा । लेकिन ऐसा मानना कि चाहे जितना किसान बोये उनको ऊंची कीमत मिलती रहे तो इस भ्रम से जितनी जल्दी यह दूर होंगा उतना ही सब के लिए ठीक होगा । आखिर इस चीनी का, गुड़ का या खांडसारी का देश क्या करे । या तो देश में ही उसकी आवश्यकता हो या विदेश में मांग हो । आज न देश में उसकी आवश्यकता है और न विदेश में मांग है । उन्होंने बड़े दाव के साथ कहा कि हम जब थे तब 500 करोड़ रुपये का हमने निर्यात किया था । श्रीमन्, उस समय इन्टरनेशनल मारकेट मे चीनी 700 पाऊंड प्रति टन के हिसाब से चीनी बिक रही थी, उस समय उसका लाभ उठाने की कोशिश की गयी और यह ठीक किया गया लेकिन आज 700 पाऊंड प्रति टन की बजाय 100 पाऊंड प्रति टन है यानि 1/7वां मूल्य हो गया है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसलिए वहां चीनी बेची नही जा सकती है ।

गुड का जिक्र किया गया कि गुड़ विदेश नही जाने दिया । गुड की मांग रही नही है । किसी भी पिछले साल में 10 हजार टन से ज्यादा गुड़ कभी इस देश से बाहर नही गया है, गुड़ खाने वाले नहीं है । गुड़ क्यो खायेगा । अगर आज आपने बाजार मे गुड खरीदा जाय 80, 90, 100 रुपये क्विंटल और उस पर सारे खर्चे जोड़ जाये तो विदेश पहुंचते पहुंचते उसका मूल्य 140–150 क्विंटल से कम नही रहेगा और जब उनको 160 रुपये क्विंटल पर अच्छी चीनी, बढ़िया मिल रही है तो कोई क्यों खायेगा गुड़ । इसलिए यह सारा भ्रम है कि हमने रोक दिया था । हमने तो सारा खोल रखा था थोड़ी देर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने सारे आंकड़ देख है, किसी भी वर्ष गुड़ यहा से 10 हजार टन से ज्यादा नहीं गया और न उधर उसकी संभावना है और विशेषकर इसलिए कि जब चीनी के दाम इतने गिर चुके हैं कि उसके मुकाबले लोग चीनी खाना ही ज्यादा पसंद करेंगे ।

अब मैं गन्ने के मूल्य के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि इस वर्ष पिछले वर्ष से कुछ ज्यादा ही मिला है किसानों को, कम नही मिला है । बात कही जाती है कि पहले चीनी की मिलों में पेराई शुरू होनी चाहिए थी । इस बात को मै स्वीकार करता हूं लेकिन मै यह बतलाना चाहता हूं कि पिछले किसी वर्ष में जिसकी आप बहुत प्रशंसा कर रहे है, 2 लाख टन से ज्यादा उस अवधि में चीनी नही बनी है । हमने उसके मुकाबले में 20 लाख टन चीनी अधिक पैदा कर दी है । यदि मान लीजिए हम नवम्बर में शुरू करते हो ते तो फर्क दो लाख टन का पड़ता है लेकिन उस 2 लाख के मुकाबले हमने 20 लाख

टन ज्यादा चीनी पैदा की है और आप इसलिए नहीं करते थे कि किसानों को लाभ पहुंचे बल्कि उस समय अवसर था विदेशों को भेज कर विदेशी मुद्रा कमाने का इस लिए एक्साइज ड्यूटी में रिलीफ दिया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा चीनी जल्दी से जल्दी पैदा हो और विदेशों में बेच कर फारेन एक्सचेंज कमाया जाय आज । वह स्थिति नही रही न तो विदेशी मुद्रा की इतनी आवश्यकता है जितनी उस समय आपको थी । लेकिन फिर भी मै मानता हूं कि इस गन्ने के बढ़े हुए प्रोडक्शन को देखते हुए शायद यह अच्छा होता कि पहले फैक्टरियां शुरू होती । लेकिन उसमें भी भारत सरकार का दोष नहीं है । जब फैक्टरियों के बीच, गन्ना उत्पादकों के बीच राज्य सरकारों के बीच काफी लम्बे अर्से तक यह निर्णय नही होता कि किस भाव पर गन्ना बिकेगा, वहां बारगनिंग शुरू होती है और उस बारगेनिंग में देरी होती है परन्तु फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष हम लोग इस बात का पूरा प्रयत्न करें कि फैक्टरिया जल्दी से जल्दी चले क्योंकि अगले वर्ष भी स्थिति कुछ भिन्न होने वाली है ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं यह जो कठिनाइयां इस वर्ष दिखाई देती हैं, वह भी रहेंगी ।

अब गन्ने के मूल्य की अदायगी के बारे में मै कहना चाहता हूं कि अब तक हमारा सारा प्रयत्न इस बात की ओर केन्द्रित था कि हम ज्यादा से ज्यादा गन्ने की पेराई करवा सकें । इसलिए हमने ज्यादा डिस्टर्ब नही किया । क्योंकि गन्ना जितना ही निकल जाय उतना ही अच्छा है । लेकिन अब वह काम समाप्त हो गया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ताकत है हुकूमत की वह सारी लगाकर, सारे उपाय करके किसानों को गन्ने की कीमत जल्दी से जल्दी दिलाई जायगी ।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, I do not want to enter into the political gimmicry but I want to bring you to the rational aspect of the sugar crisis in the country. You have wrongly stated now; (do not be politically pressurised) to advise the sugar factories to start crushing in September. This will be a total national waste by burning sucrose which is valuable. I would like to persuade my friends on this side and you also through your Ministry persuade the cane growers that the recovery in September-October is not more than between 7 to 8.5. In Maharashtra we have studied this problem and the State *Government has issued directives to* co-operatives to start crushing only by October end because between November and May the recovery is the maximum. Otherwise, you will be burning sucrose in sugarcane. For Heaven's sake do not do that.

Now, I would like to come to the point which my hon. friend has pointed out. The real difficulty starts with the fixation of attractive prices of sugarcane growers by the State Governments. That is the real malady. The trouble starts when the prices are fixed, leave aside your APC formula, naturally the prices of sugar are worked on the actual price paid to cane growers which is between Rs. 13 and Rs. 16 per quintal. Once you fix the price, naturally that fixation is done on certain *ad hoc* decisions of State Govt. This results in the price being different from State to State. The prices of Sugar in Haryana, Punjab, Eastern U.P., U.P., Andhra Karnataka, Gujarat, Maharashtra are irrational as they are based on *ad hoc* cane price and Marathe Committee or RCP formula was sacrificed due to political pressure. Particularly from the place from where you come, the price unfortunately was given more and you could get between 300 and 400 as levy price. Nowhere that is possible in the country. But I do not blame you. You were not there, I know that. I am not going to take that report of the Amrit Bazar Patrika wherein it is said that Mr. Bhanu

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

Pratap Singh comes from U.P. or that Mr. Shanti Bhushan belongs to the Thapar group, I do not want to say that also.

SHRI KALP NATH RAI: What has the Thapar group to do?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Thapar Group has sugar mills. That is why their interest is also protected at high places.

SHRI KALP NATH RAI: They are protecting the interest of the Thapar group. They are the agents.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: They are all mill *maliks*. वह तो सब लोग हैं भाई मिल-मालिक । सबको खिलाते हैं। मिल-मालिक के पाकेट में पालिटिकल पार्टी रहती हैं ।

Mr. Minister, I would like to inform you that because of the political pressures you have not relied on the Marathe Committee's formula and that is why this whole trouble has started. You please rely on the Marathe Committee's formula. Otherwise, your problem in Eastern U.P., Western U.P. will remain there. Your problem with Thapar group in Punjab and your problem in Haryana will remain there and we in Southern States are the casualties of your wrong policies and infighting which is going on among yourselves. Therefore, I would like you to give a promise today that the Marathe Committee's formula or the Bureau of Industrial Costs and Prices formula, or whatever it is, will be adhered to and a rational decision will be taken to fix sugar prices.

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): Although Karnataka gets 8.5 recovery the sugar price there is the lowest.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Then you have to look to the other aspect of the sugar crisis. Leave aside the question as to how you are going to work out the formula, I want the assurance that the Marathe Committee's formula will be adhered to. If you go to fix arbitrary prices. Nothing else. The Southern States will revolt. Your problem is political. You educate the agriculturists about better land use to avoid overproduction in U.P., Bihar. By growing wheat twice, they can earn more than what they can earn from sugarcane. That you have to tell your own people and the cane-growers and not encourage to grow more sugarcane by agreeing to pay for and increase price to cane. (*Time bell rings*) Sir, I have got five minutes more. I want to be more disciplined.

So, Sir, better land use is the real reply for this difficulty. But the Marathe Committee formula must be assured; otherwise you cannot solve this problem. The hon. Minister knows that the sugarcane growers have not received the money. Two days back, Mr. Barnala said that within 15 days they would pay. Today the dues are Rs. 130 crores all over the country. I, as a cooperator, know that many cooperatives have not paid and many of the cooperatives will not be able to pay. Not because we are defaulters, but because we have no money. We are your buffer-stock holders. You have stocked so much sugar that about Rs. 1000 crores are locked at factory point. Would you assure that a soft loan will be given to the sugar factories for their buffer-stock and you will release the balance funds so that we can pay to the sugarcane growers? The growers are our very poor patrons. We must pay them. At least you should assure us today that a soft loan will be arranged within 15 days. We cannot pay; so some such assurance has to come from you.

Another point that I want to make is that there is the statutory responsibility to pay within 15 days. Have you ever complained against or pro-

secuted any private sector mill or anybody for not paying within 15 days —say Kanorias, Thapars or anybody? Have you? Be categorical. I know you have not, because you cannot. There is no money with them also. But the point is that they have also no money for that purpose. Money has to be found out.

And the last point—I do not want to take more time—Mr. Minister, is that it seems now that the better land use formula is not being used. The cane-growers were induced because fancy prices were assured by pressurising the State Governments. And Mr. Kalp Nath Rai, just listen to this; this is for your information. The co-operators have also not paid. Co-operators are sufferers. We cannot pay more than Rs. 110 to 140 in Maharashtra where the average recovery is 11.7 per cent. And in U.P., the recovery must not be more than 9 per cent. How can you pay Rs. 140 or Rs. 160? Nobody can pay. So, Sir, what I want to say is that you cannot pay for that purpose. Similarly money has to be found to create buffer-stock and pay growers. Mr. Bhanu Pratap Ji the crushing starts again in the months of September, October and November. The mills have to have their own programme. You have to assure that as in the case of Sampath Committee some concessions were granted, some more concessions will have to be worked out—not for the mill *maliks* but for the sugarcane growers—in whatever way you like. You have to announce these concessions. Mr. Barnala said that these steps will be for the next season. I know that, but you have to say now that sugar is going to be decontrolled. We are squeezed—and not only squeezed, we have not got a single farthing in the factory to pay to the cane-growers, or the suppliers of cane. This is our crisis. Straight replies are really required to solve this crisis and a rational approach is necessary.

Lastly, Sir, in West Bengal the Amitpur Mill—Mr. Banerjee told me —which is a State sector mill has not paid for the last 3 months. What type of statutory authority have the Government got? The same is the case elsewhere. So, an immediate relief of about Rs. 1000 crores for all these sugar mills to pay their dues to the sugarcane growers, a policy of decontrol of sugar and educating the people in the north that it is not profitable—all this is required to be done. You educate them, Mr. Bhanu Pratap Singh, that by growing wheat twice, or having rice thrice, the agriculturists can earn more than what the sugarcane gives. Tamil Nadu has shown this; Andhra Pradesh has shown this.

1 P.M.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, I am sorry the hon'ble Member misunderstood me. I do not propose to succumb to the rhetoric of Mr. Kalp Nath Rai and I do not propose to get these factories started in September. It will be only in November.

Regarding rational basis for fixation of sugarcane prices, let me inform the House that as far as the Government of India is concerned we only fix the statutory minimum prices ...

SHRI KALP NATH RAI: What is the price?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: That is only Rs. 8.50 to link to the recovery of Rs. 8.5 per cent.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: How the State Government paid the price?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It is arrangement between factories, growers and the State governments. That is the difficulty. They have arrived at a different arrangement and it so happened that the State Governments in the North could force the factories to pay a higher price.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): No, Sir. That is not correct. You have fixed Rs. 2.60 for North Bihar and Rs. 1.60 for Andhra. How could they pay more? It is your mistake. You have to rectify it.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I am talking about cane price, not the levy price.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: You can pay the price only when you get more levy price.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I am dealing with levy price just now.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: Your department has completely failed in fixing the price.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: As far as the cane price is concerned the Union Government fixes only the statutory minimum price which is Rs. 8.50 for a recovery of 8.5 per cent. If any other prices are paid in any States it is as a result of agreements arrived at in the States between the factories, the State Government and the cane growers there.

As far as the levy price is concerned, let me tell you that there is no interest involved in raising the price here or in Bihar or the Thapar group or this group or that group. If these levy prices are unjust, and unfair, all that we have done is to increase it to by Rs. 18 and a few paise across the board.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Mr. Bhanu Pratap Singh, please do not mislead the House.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: The Minister is ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish first.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: That is not correct ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not interrupt in between. Order, please.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: All I am saying, Sir, is that I am not justifying this price at all. I am saying that if it was unjust and unfair, it was also so in the past. All that we have done is to increase it by Rs. 18... (*Interruption by Shri N. P. Chengalraya Naidu*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not interrupt, please. This is not the way to proceed.

SHRI KALP NATH RAI: Mr. Naidu is correct.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not provoke him.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: I have given a Calling Attention notice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not the way to speak. Every minute you are getting up, Mr. hon'ble Member.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I would like any hon'ble Member to point out any factory where a change in levy price has been more or less than the fixed one, that is, Rs. 18.

I agree with my hon'ble friend here that even the well-wishers of farmers should now advise them to reduce the area under sugarcane. If they do not it voluntarily...

SHRI KALP NATH RAI: On a point of order.

श्री उपसभापति : सुनने दीजिए। उत्तर तो आ जाने दीजिए।

श्री कल्प नाथ राय : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। यह सरकार की जिम्मेदारी है ...

श्री उपसभापति : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री कल्प नाथ राय : यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि . . .

श्री उपसभापति : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है। बार बार आप के लिए ऐसा बोलना ठीक नही है। आप 25 मिनट तक बोले और किसी ने इंटरेप्ट नहीं किया। यह कोई तर्क नहीं है। प्वाइंट आफ आर्डर के नाम पर आप हर बार इंटरेप्ट नहीं कर सकते। आप इनको खत्म करने दीजिए . . (*Interuptions*) माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। यह बहुत गलत तरीका है।

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, I have already said that the pricing of sugarcane is a subject of the State because different States take different decisions. I am in full sympathy with my hon. friend there that a more rational basis should be evolved and I intend to do so. But it will be premature for me to say anything just now unless a final decision in the matter is taken. Similarly, about the levy price. I can assure the House that a more rational basis will this year be evolved for the fixation of levy price if it is to be fixed at all.

SHRI KALP NATH RAI: Thank you very much.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: It will be fixed only if we continue the dual pricing system. But should we decontrol it, then of course this question will not arise. I do not wish to say anything just now whether decontrol will be made or dual pricing will continue. It is under the active consideration of the Government and unless a decision is taken by the Government, I cannot say anything. But if dual pricing is to continue, then a more rational basis for the fixation of levy price will be evolved.

As regards provision of finances to the factories to enable them pay cane dues, I have already mentioned in my statement that all that is possible will be done. That includes your suggestions also.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): Does it include private factories, co-operative factories and mixed factories?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: As far as the Government is concerned and as far as the interests of the cane growers are concerned, we do not make any distinction. They should all have the finances to pay the cane growers.

SHRI N. G. RANGA: And they will have to pay 15 per cent interest on arrears.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Yes, that they will have to.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: One instance of a factory not paying dues for a long time has been given and I have been asked, "Why don't you exercise statutory authority?" I have only to say that whatever authority we exercise, we do so only through the State Governments, and we are pressing them hard. Every fortnight we are writing to them and we are doing our best possible. As I have earlier assured, we wlll leave no stone unturned to see that cane dues are paid to the growers as soon as possible.

SHRI SUJAN SINGH (Haryana): Sir, the crisis in the sugar industry today is not a crisis of the farmers alone. Today it has assumed the character of a national crisis and therefore I would request the Opposition Members as well as the Members of the ruling party not to consider it as a way to gain any political advantage because the nation is

[Shri Sujan Singh]

at stake and the national economy is at stake. I am a farmer myself and I have all along been advocating the cause of the farmers. Today I have stood up not only to advocate the cause of the farmers but also to request to consider as to how this lot of the economy can be improved. By offering a few more rupees to the farmers or by condemning the sugar industry our problem cannot be solved because there are three things involved in this crisis. First is over-production. Second is less off-take of sugar in the world or in the open market. Third is a very important point: We should impress on the farmers that they should have less area under sugarcane cultivation. The Government should try its best to see that the off-take, that is, consumption in the country, increases and somehow see that foreign countries are persuaded to purchase our sugar. As the hon. Minister has pointed out, the rate of sugar in foreign countries is much less than before; it is one-seventh as compared to the previous rate. Sir, when we are purchasing goods worth so many thousands of crores of rupees from foreign countries, can we not persuade foreign countries to take sugar from us in exchange for the goods that we are getting from them as a barter? If that is not possible, then it is a serious problem. Now, when the hon. Minister was giving us the explanation today, I had a feeling that he himself is helpless in this situation. If that is the position, let him admit his helplessness in the matter and let the Members of the ruling party and the Opposition Members sit together—and, if need be, associate industrialists also with them—to find out how we can produce sugar in the country at a less price. The cost of sugar production should also be less because when we are facing a crisis in the international market and we are not able to compete with foreign countries how can we go on purchasing sugar at high price paying more money to the farmers and putting our mills in an uneconomic position? All those factors which are responsible for producing sugar at a higher cost should be reviewed and let us find out a way by which sugar could be produced cheaper in the country so as to compete with foreign countries. Foreign countries are not going to take mercy on us. When we are producing sugar at a high cost, why should they take it from us? Therefore, these are the problems which we have to face boldy and we should not mislead the people that we are not mislead the people that we are unable to face competition in the international market.

With these few words, I will suggest the Government to take this matter very seriously, because in the last session also we were told that the Government was aware of the difficulties and was considering the matter. Out of the year, only three months are left now. Only discussions or counter questions or allegations will not take us further. It is high time that immediately the Members of Parliament from both sides sit together and help the Government so that we can compete with foreign countries in respect of sugar, we are able to export more sugar somehow or other and we are able to reduce the area under sugar-cane. If need be, we should pass some Bill not only for sugar-cane but also for wheat and cotton because we are going to face difficulties in the near future there also.

Thank you.

SHRI G. C. BHATACHARYA (Uttar Pradesh): In connection with this, I have to make only one point, so that he may reply that also along with the other points. I am only saying ...

श्री उपसभापति : हम एक तरतीब से चल रहे हैं। आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I am not saying that I want any chance. I am only saying that it is in connection with that so that he may reply together.

श्री उपसभापति : मैं आप से फिर निवेदन करूंगा कि जिन्होंने नाम दिया हुआ है उनके बोलने के बाद आपको भी बोलने दिया जाएगा ।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I do not want to speak. I want only to make a suggestion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is the same thing as giving a suggestion. There are a large number of people on the waiting list who are waiting as anxiously as you are to participate in the discussion. They have given their names in advance.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I do not want to participate ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I only request you to please keep the rules in mind. If you are interested in any subject, please give your name in advance so that the Chair is properly warned as to who wants to speak and he sets the whole thing in such a way that everyone gets full satisfaction.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: May I just point out one thing? Is the rule which you are mentioning applied uniformly? I have been seeing day after day that different persons who have not given their names also speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: And, secondly. I do not want to speak. I only want to . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will not let it go unrebutted like this. Please resume your seat. I only request you to please consult your Chief Whip before you want to give your name. We have a certain procedure in this House.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I should be applied uniformly in case of everybody.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is applied to everybody.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: We have seen how this is applied. Just because we are keeping quiet, it does not mean that we should be neglected.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. Everyone has given his name from every party who will speak from his party in this debate. And I am going according to that. I request you to consult your Chief Whip.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I know that. I have nothing to say in that regard. I am only saying that those persons who do not give their names also participate. (*Interruptions*) I only want to make a suggestion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everyone wants to make a suggestion. Mr. Indradeep Sinha is quietly, very sincerly sitting from the beginning.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I do not want to take his time ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are taking his time. Hon. Member, that is what you are doing.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : श्रीमन्, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है । जो बात अभी सदन में उठ रही है वह पहले भी उठी है । आप जानते हैं कि काल अटेंशन में बहुत से नाम रहते हैं और जिन लोगों के नाम होते हैं उन सब को बोलने का मौका नहीं मिलता है । लोक सभा में यह पद्धति है कि पांच नाम लाटरी से निकाल कर रखे जाते हैं । लेकिन हमारे इस सदन में पार्टीवार नाम लिये जाते हैं । हम चाहते है कि जितने आदमी

[श्री शिव चन्द्र झा]

बोलना चाहते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए । हम यह भी चाहते हैं कि काल अटेंशन में जो नाम होते हैं कम से कम उनको तो बोलने का अवसर मिलना चाहिए । अभी स्थिति यह है कि जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है, उनमें असंतोष छा जाता है । इसलिए आप अगर इस पद्धति में परिवर्तन लाने पर विचार करें तो अच्छा रहेगा । काल अटेंशन पर बोलने के लिए अगर लाटरी से पांच आदमियों के नाम निकाल लिये जायें तो किसी को असंतोष नहीं होगा और सब काम ठीक प्रकार से चल सकेगा ।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Mr. Deputy Chairman, Sir, when the Calling Attention motion on the correspondence between the Prime Minister and the ex-Home Minister was there, may I know how many Members adhered to that rule? There were many Members who spoke. (*Interruptions*) The Chair was pleading with them. But you allowed them to speak. Now, you will not allow me to put forward a suggestion? I only want to give a suggestion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I requested you. You will get your chance. But let us go according to the list first. I never told you not to speak.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I do not want to speak. I want to make only a suggestion. (*Interruptions*) I am trying to facilitate your job, but I do not know how you are taking it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My difficulty is, everyone wants to make a point and then makes a speech. How do I know who will not make a speech. If I start allowing Members and they go on for more than a minute, how can I say "No, you have not made your point? So I requested you to please let me go according to the list.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: If I take more than a minute, you can ask me to sit down. How do you know I will take more than one minute?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not have such sort of a debate on the floor of the House. The Minister.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: My hon. friend, Mr. Sujan Singh, has made some sugestions and some of them are very good I will certainly take them into consideration. He said that the consumption of sugar should be increased in the country. Last year the consumption was 37.5 lakh tonnes and this year it is going to be in the neighbourhood of 46 lakh tonnes. So there has been a substantial increase in the consumption within the country. I may also inform the House that together with *gur*—I mean, taking all the sweetening agents into consideration—our *per capita* consumption in this country is not less than the international average consumption of sugar. Nevertheless we are trying to increase our consumption and we are also trying to increase our exports. In spite of the prices that I mentioned before, we have decided to export 6.5 lakh tonnes of sugar even at a loss of Rs. 30 crores. So, as I have said earlier, we are doing all that is possible to alleviate this difficult situation.

श्री इन्द्रदीप सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसको मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे मूल समस्या का समाधान नहीं होता है और न ही समस्या के समाधान का कोई संकेत मिलता है । मंत्री महोदय कहते हैं कि मूल समस्या यह है कि हमारे देश में गन्ने की पैदावार ज्यादा हो गई है, चीनी की पैदावार ज्यादा हो गई है और

इसका कोई रास्ता दिखाई नही देता है। मैं उनसे इस बारे में सहमत नहीं हूं। हमारे देश में अगर चीनी की खपत कम है तो इसका प्रधान कारण है कि चीनी का दाम बहुत ऊंचा है। साधारण लोग इसको खरीद नहीं सकते। मन्त्री महोदय ने पता नहीं कहां से आंकड़े लिए। होलसेल मार्केट के आंकड़े लिए होंगे कि 80 रुपये प्रति क्विंटल चीनी दाम गिर गया है। लोक सभा में एक माननीय सदस्य ने कहा कि सुपर बाजार, दिल्ली में अभी भी चीनी का दाम चार रुपये अस्सी पैसे प्रति किलोग्राम है। तो दाम ऊंचे बना कर रखे गए हैं। यह सरकार मिल वालों के साथ मिल कर दामों को बढ़ाती है, बनावटी तौर पर ऊंचा चढ़ा कर रखती है। कुछ दिन पहले दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा घटा कर 1000 ग्राम से 900 ग्राम कर दिया; क्योंकि उनको चीनी कम दी गई जब कि देश में इतनी चीनी है। मन्त्री महोदय शिकायत कर रहे है कि चीनी की खपत में कमी हो गई है। तो फिर दिल्ली में खपत की कटौती क्यों की गई है जिसको ले कर राजनैतिक दलों और सार्वजनिक संगठनों ने अखबारों में निन्दा करते हुए बयान दिए है। यह मिल वालों की साजिश है। उनकी यह नीति है कि चीनी कम उपलब्ध हो, देश में भले ही ज्यादा पैदा हो, उनके गोदामों में पड़ी रहे, लेकिन बाजार में चीनी न आने पाए। बाजार में इसके ज्यादा से ज्यादा ऊंचे दाम बने रहें। तो बाजार में दाम ऊंचे रखने की मिल वालों की नीति है जिसमे कांग्रेसी सरकार भी शरीक थी और यह जनता सरकार भी शरीक है। यह इसी नीति के कारण है कि चीनी और ईख का "ओवर प्रोडक्शन" दिखाई पड़ता है। वास्तव में कोई "ओवर प्रोडक्शन" नही है। अगर सरकार की नीति बदली जाए तो यह समस्या हल हो जाएगी और सरकार की नीति अगर नहीं बदली तो कुछ और होने वाला है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा।

श्री प्रेम मनोहर (उत्तर प्रदेश) : यह तो ओवर प्रोडक्शन के आंकड़े है।

श्री इन्द्रदीप सिंह। आंकड़े हमारे पास भी हैं। देश की 60 करोड़ जनता है। इस समय 'पर कैपिटा' कंजम्पशन चीनी का सात किलोग्राम से घट कर छः किलोग्राम हो गया है और भी घटता जा रहा है। आंकड़े हमारे पास भी है। यहां के लोगों को चीनी नही मिलती है। चीनी दबा कर, महगी कर के रखी जाती है। मिल वाले मुनाफा कमाने के लिए करते है। वे चीनी बेचने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। चीनी जनता को उपलब्ध कराने में दिलचस्पी नही रखते है। वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने में दिलचस्पी रखते हैं। यह प्रधान कारण है।

अब मैं दामों के बारे में आता हू। श्री रफी अहमद किदवई जब केन्द्रीय सरकार में कृषि मन्त्री थे तो उन्होंने दामों का एक मोटा फार्मूला दिया था। जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन ईख का दाम दो। इस फार्मूले के मुताबिक चीनी के एक्सफैक्टरी प्राइस का 1/16 शुगरकेन का प्राइस होना चाहिए। सरकार ने लेवी शुगर का एक्स-फैक्टरी प्राइस 168 रुपये रखा था। उस हिसाब से 16 रुपये 80 पैसे शुगरकेन का मिनिमम दाम होना चाहिए। इसके मुकाबले में सरकार ने तय किया साढ़े आठ रुपये क्विंटल। पिछले साल एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने सिफारिश की थी कि शुगरकेन का कल्टीवेशन का खर्च बढ़ गया है इसलिए गन्ने का दाम एक रुपया बढ़ा दिया जाए अर्थात् साढ़े आठ रुपये से साढ़े नौ रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाए परन्तु सरकार ने नही माना। लेकिन सरकार ने मिल मालिकों को रियायत दी, लेवी शुगर पर ड्यूटी घटाई, फ्री मार्केट शुगर पर ड्यूटी घटाई और श्री भानु प्रताप सिंह जी ने इसी सदन में कहा था कि 85 करोड रुपये मिल मालिकों को इससे मुनाफा होगा। इसके बाद फरवरी में . . .

(Interruptions)

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं ने कहा।

श्री इंद्रदीप सिंह : एक बार डिबेट में आपने हो कहा था। आप बतायेंगे आपका कितना एस्टीमेट है ?

एक्साइज ड्यूटी लेवी शुगर पर 10 परसेंट से 7.5 परसेंट को और फ्री सेल शुगर पर 37.5 परसेंट से घटाकर 20 परसेंट की। उससे कितना रिलीफ मिला मिल मालिकों को यह आप बतायें ? तो उनको आपने रिलीफ दिया और उनको फिर रिलीफ दिया जब लेवी शुगर का दाम 2 रुपये 15 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 30 पैसे प्रति किलो कर दिया यानि क्विंटल में आपने 215 से 230 रुपये कर दिया। उसमें कितना आपने रिलीफ दिया ?

लेकिन किसानों के साथ क्या किया ? गन्ना उत्पादकों के साथ क्या किया ? एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन ने कहा कि एक रुपया बढ़ा दो, उसको भी आपने ठुकरा दिया और मिल मालिकों के साथ सौदेबाजी करते रहे, जिस कारण से एक महीने तक मिलें नहीं खुलीं और बहुत सा गन्ना पड़ा रहा, गन्ना जलाया किसानों ने। मन्त्री महोदय कहते हैं कि जितना बाउंडेड केन था वह ले लिया गया। मैंने "इकनामिक टाइम्स" में रिपोर्ट पढ़ी है कि 15 परसेंट बाउंडेड केन भी यू०पी० में क्रश नहीं हुआ, वह खेतों में खड़ा रह गया, उन इलाकों में जहां फैक्टरियां बन्द हो गयीं। मन्त्री महोदय इसका जवाब देंगे ?

इसलिए शुगर केन प्राइस क्या होना चाहिए ? शुगर केन प्राइस कम से कम इतना जरूर होना चाहिए जितने से किसान गन्ने की खेती कर सकें। वह दाम अगर नहीं दिया जायेगा जिससे कि किसान गन्ने की खेती नहीं कर सकेंगे, तो कुछ दिनों के बाद चीनी का संकट फिर देश को भुगतना पड़ेगा। 1960–70 के बीच में चीनी की सालाना पैदावार 21 लाख टन और 42 लाख टन के बीच चढ़ती उतरती रही है। जब गन्ने का दाम अच्छा दिया तब पैदावार बढ़ी और जब गन्ने का दाम घटा दिया तब पैदावार घट गयी। तो आप अगर गन्ने का दाम घटाइयेगा तो किसान भी इसका जवाब जानता है। फिर आपकी पैदावार घटेगी और फिर देश में चीनी का संकट होगा।

और मैं यह तथ्य आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की चीनी की इकनामी नार्थ इण्डिया से डिसाइड होती है। गन्ने का 51 फीसदी रकबा उत्तर प्रदेश में है, आन्ध्र में यह 4 परसेंट, कर्नाटक में 4 परसेंट, तमिल नाडु में 4 परसेन्ट। वहां एरिया बहुत कम है मगर पैदावार ज्यादा है। महाराष्ट्र में 8 परसेंट, हरियाणा में 6 परसेंट। इस प्रकार 51 परसेंट एरिया आपका उत्तर प्रदेश में है। तो अगर उत्तर प्रदेश के किसानों को आप गन्ने का लाभदायक मूल्य नहीं दे सकते तो चीनी का संकट आपका दूर नहीं हो सकता। साउथ इण्डिया के प्रोडक्शन से। क्योंकि एरिया बहुत कम है वहां गन्ने का और यह उत्तर प्रदेश में जो किसान खेती करते हैं वह किस टाइप के किसान है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का 64 फीसदी रकबा उन किसानों के हाथ में है जिनके पास 4 हैक्टेयर से कम जमीन है। 10 एकड़ से कम जमीन है, ज्यादातर छोटे और मझोले किसान गन्ने की खेती करते हैं। बिहार में 57 फीसदी गन्ने की खेती 4 हेक्टेयर से कम जमीन में है। तमिल नाडु में 60 फीसदी 4 हेक्टेयर से कम जमीन में है, आंध्र में 55 फीसदी 4 हेक्टेयर से कम जमीन में है। ज्यादा जमीन वाले भी कुछ राज्यों में, प्रमुख रूप से गन्ने की खेती में लगे हुए महाराष्ट्र में 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले 64 फीसदी गन्ने के रकबे में खेती करते हैं। हरियाणा में 67 परसेंट, पंजाब में 60 परसेंट, कर्नाटक में 86 परसेंट। तो यह बड़े-बड़े भू-स्वामी लोग भी खेती करते हैं

ट्रैक्टरों से। इन लोगों ने कोआपरेटिव मिलें बना रखी हैं। अखबार वालों ने उनका नाम दिया है कोआपरेटिव बुर्जुआजी। कोआपरेटिव बुर्जुआजियों की कुछ मांगें है। सरकार के सामने, हम लोगों ने जिन्हें सुना है यहां पर। इण्डियन शुगर ओनर्स मिल एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में कोआपरेटिव मिलों में 1975–76 में 17.35 रुपये, 1976–77 में 16.60 रुपये और 1977–78 में 16.20 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का आरम्भिक दाम दिया। तो मैं पूछता हूं कि आप नार्थ इण्डिया को क्यों नहीं सही रेट दिलाते हैं जबकि महाराष्ट्र के कोआपरेटिव मिल यह रेट्स दे सकते हैं और उसके बाद भी मुनाफा कमा सकते है। तो यही रेट आप नार्थ इण्डिया की मिलों से क्यों नही दिलाते, यही रेट आप साउथ इण्डिया की मिलों से क्यों नही दिलाते। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह जो सारा प्रपंच खड़ा कर रखा है कि आप मिनिमम प्राइस फिक्स कीजियेगा। इसके बाद प्रोविन्शियल गवर्नमेंट एक्चुएल प्राइस फिक्स करेगी और तब मिल-ओनर तय करेंगे कि कितना गन्ना खरीदें या नही खरीदें, कब पैसे दें या न दें। यह सारा झमेला खत्म करके केन्द्रीय सरकार को पूरे देश के लिये एक प्राइस फिक्स करनी चाहिये शुगरकेन की। इस प्राइस पर शुगरकेन मिल वाले खरीदेंगे, चाहे प्राइवेट सैक्टर में हों या कोआपरेटिव सैक्टर में हों, चाहे स्टेट सैक्टर में हों और किसानों को यह दाम मिलेगा।

इसी तरह से जो ड्यूअल प्राइस का सिस्टम आपने कर रखा है चीनी के लिए—ड्यूअल प्राइसिंग के चलते साउथ इण्डिया के मिल वालों को शिकायतें है। उनकी मिलें नई हैं, उनकी मशीनरी ज्यादा अपटुडेट है, उनका साइज इकनामिक है। यह जो नार्थ इण्डिया के मिल मालिक हैं—बिड़ला, थापर और कानोडिया—यह सारे के सारे जोंक हैं। 10, 12, 15 लाख रुपया लगा कर इन्होंने एक-एक कारखाना खड़ा किया और साल में 15–15 लाख का ब्लैक मार्केटिंग करके मुनाफा उठाते है और अब पैसा उसमें नही लगाते। तमाम मिलें बीमार पड़ी हुई हैं। तो इसका क्या उपाय है? आप कहते है किसानों से कि गन्ने की खेती कम करें। उससे क्या समाधान होगा। उससे यह जो दुःखी, सड़ी हुई फटीचर चीनी मिलें है उन्हें इकनामिक नही बना सकते। अगर किसान गन्ना बोना छोड़ दें, 60 प्रतिशत एरिया मे गन्ने की खेती कम हो जाए नार्थ इण्डिया में, तो क्या 40 प्रतिशत मे गन्ना होने से देश की चीनी का संकट हल होगा?

सरकार मे विचार हो रहा है, भानु प्रताप सिंह ने भी इशारा किया कि हम डी-कन्ट्रोल कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि मिल मालिकों में दो गिरोह हो गये हैं। एक गिरोह कहता है कि डी-कन्ट्रोल होना चाहिये, दूसरा कहता है कि ड्यूअल प्राइस रहनी चाहिये। मिल-मालिकों के दो गिरोहों की लड़ाई सरकार के भीतर भी हो रही है। दोनों के नुमाइन्दे सरकार में मौजूद हैं और वहां यह लडाई लड़ी जा रही है।

मै सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि मिल मालिकों के दबाव में आ करके आपने यदि डी-कन्ट्रोल किया और गन्ना उपजाने वाले किसानों को उनका मुनासिब दाम नही दिया तो पूरे भारत में इस सवाल को लेकर महाभारत मचेगा और जनता पार्टी की सरकार गन्ना किसानों के क्रोध की आग में जल जायगी, यह सरकार बच नहीं सकती, उसके बाद, सोचना पड़ेगा कि रास्ता क्या है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाई थी कि चीनी उद्योग का क्या किया जाए। उस कमेटी ने विभाजित रिपोर्ट दी, आधी ने कहा चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये, आधी ने कहा नहीं करना चाहिये। मैं सरकार से अभी भी मांग करूंगा कि यदि चीनी उद्योग

[श्री इन्द्रदीप सिंह]

को बचाना चाहते हैं, गन्ने की खेती को बचाना चाहते हैं, करोड़ों किसानों की जिन्दगी को बचाना चाहते हैं तो चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ड्यूअल प्राइसिंग का सिस्टम समाप्त किया जाए, चीनी की जितनी पैदावार हो सारी ले ली लीजिये और मुनासिब दाम पर पूरे देश में बेचिए। विदेशों में अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा कि प्रति टन 100 पाउंड अब भी रेट है चीनी का, जो रु० 150 प्रति क्विंटल पड़ता है। आपके यहां भी लेवी शूगर का रेट रु० 168 था। अभी आपने मिल मालिकों को खुश करने के लिए थोड़ा बढ़ाया है। हमारा उत्पादन खर्च घट सकता है, अगर बाइ प्रोडक्ट्स मौलेसीज़ और बेगास का प्रापर यूटिलाइज़ेशन हो। और फैक्ट्रीज मार्डनाइज हो जाएं, तो हमारा कास्ट और भी घट सकता है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम प्रतियोगिता कर सकते हैं।

इसलिए आप ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम समाप्त कीजिए, पूरे भारत में गन्ने का यूनीफार्म दाम केन्द्रीय सरकार तय करे और सभी मिलों से वह दाम दिलवाये और 15 दिन में यदि मिल-मालिक पेमेन्ट नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद आप किसानों को यह हक़ दीजिए कि अपनी पुरजी ले जाकर एस०डी०ओ० को दाखिल कर दें और उनसे दाम ले लें और एस०डी०ओ० जाकर उनसे वसूल करे। एक केन-ग्रोअर मैं भी हूं, मेरा भी गन्ने का दाम बाकी है; सुना है थापर ग्रुप का कोई एजेंट है जो आप की सरकार में है, मैं स्वयं नहीं जानता कौन एजेंट है। थैकर ग्रुप के एक कारखाने के यहां दाम बाकी हैं, आदमी दौड़-दौड़ कर थक गया। तो यह कब तक किसान दौड़ेगा ? 10,15 और 20 मील से आता है दौड़ कर और फिर कहा जाता है अगले हफ्ते आओ। चार बार दौड़ने के बाद बैठ जाता है। आप कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए, आप पीनल इंतजाम कीजिए कि अगर वह नहीं पे करें तो दाम सर्टिफिकेट के जरिए वसूल हों। आप कहते हैं कि 15 परसेंट इन्टरेस्ट देंगे तो 15 परसेंट इन्टरेस्ट आप बैंक को देकर कर्जा दिलवा दीजिए। किसान इस फेर में कहां पड़ेगा।

अन्त में कोई भी फैसला करने के पहले मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा : आप दोनों सदनों में अपने प्रस्ताव को रख कर दोनों सदनों की राय ले लीजिए, उसके बाद चीनी और गन्ने के बारे में किसी नीति का फैसला कीजिए नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होने वाला है।

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, बहुत से प्रश्न जो पहले उठाए गए वे फिर उठाए गए, उनका उत्तर मैं नहीं दूंगा। मेरी कठिनाई यह है कि कुछ "इकानामिक टाइम्स" में पढ़ के ले लिया, कुछ किसी माननीय सदस्य ने दूसरे सदन में कुछ कह दिया और उसको सत्य मान कर आलोचना की जाती है। इकानामिक टाइम्स में छपा कि गन्ना फैंका जा रहा है। अब वह जर्नलिस्ट यही शहर के रहने वाले होंगे कभी गए नहीं होंगे देहात में मगर उनकी बात ज़रूर दोहराई जाती है सदन में। किसान इतना मूर्ख नहीं है कि गन्ना फैंक कर जाता है। अगर गन्ना खड़ा रहेगा तो तीन महीने बाद सप्लाई कर देगा। तीन महीने में उसकी कोई दूसरी फसल होने वाली नहीं है।

इसी प्रकार से यह कहा गया कि सुपर बाज़ार में 4 रु० 80 पैसे किलो चीनी बिक रही है। अब यह बिलकुल असत्य है, निराधार है। चीनी सुपर बाज़ार में भी प्लास्टिक की फैंसी थैलियों में सिर्फ 3 रु० 80 पैसे प्रति किलो बिक रही है। सारे देश में चीनी 3 रु० 60 पैसे और 3 रु० 80 पैसे के बीच में रिटेल लेबल में बिक रही है लेकिन यहां कहा जाता है 4 रु० 80 पैसा। सारे देश के आंकड़े हम ले सकते हैं--पिछले साल के और इस साल के। होलसेल का मैं बता रहा हूं दिल्ली में पिछले साल 420 रु० क्विंटल

था, इस साल 336 रु० है; कानपुर में 415 था, इस साल 325 है; बम्बई में 402 रु० था, इस साल 352 रु० है। यह अच्छे किस्म की चीनी का भाव है। मद्रास में पिछले साल 402 रु० क्विंटल था, इस साल 320 रु० है तो जब मैंने कहा पिछले साल से 80 रु० कम दाम हैं चीनी के तो मैंने गलत नहीं कहा था, जिनको यह शिकायत है कि चीनी महंगी मिल रही है, 4.80 रु० किलो। मैं तो मिल-मालिक नहीं हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं जिसको लाखों टन चीनी आज चाहिए वह 350 रु० क्विंटल में खरीद सकता है। इसलिए वास्तविकता को समझ कर किसी बात का जिक्र होना चाहिए।

दूसरी बात, एक तरफ तो चीनी सस्ती करने के लिए पैरवी होती है। मै मानता हूं, चीनी सस्ती होती है क्योंकि जब तक उसकी खपत नही बढ़ेगी तब तक देश में उसके अधिक उत्पादन की समस्या हल नहीं होगी, परन्तु उसके साथ ही साथ वे लोग गन्ने की कीमत बढ़ाने की भी पैरवी करते हैं। अब ये तीनों बातें परस्पर-विरोधी (कांट्रेडिक्टरी) बातें हैं। क्या जो अन्तिम पदार्थ है उसके मूल्य का कोई प्रभाव जो रा मेटीरियल है उस पर नहीं पड़ेगा? यह कैसे हो सकता है कि गन्ने का मूल्य बढ़ता रहे और चीनी का मूल्य घटता रहे। मगर यह एक नामुमकिन बातें भी हम से करने को कहा जाता है। इसकी भी आलोचना की जाती है, की गयी कि जब चीनी की इतनी अधिकता है तो फिर दिल्ली को क्यों कह दिया गया कि हम ज्यादा चीनी एलाट नहीं कर सकते। किस किस्म की चीनी? वह लैवी की चीनी है जो सस्ती दर पर बिकती है। उस का जितना उत्पादन है वह हम ने पूरा बांटने का निश्चय किया और हर राज्य को उस की आबादी के अनुसार 425 ग्राम प्रति मास प्रति व्यक्ति के हिसाब से बांटने का निर्णय हुआ है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। उस सस्ती चीनी के खरीदार दुनिया में बहुत हैं। मैं मानता हूं और उस सस्ती चीनी से ही हम ने निकाल कर, उस का अधिकाश भाग विदेश को भेजने का फैसला किया है। उस के गाहक दिल्ली में, मद्रास में, बम्बई में सब जगह हैं। लेकिन वह चीनी तो एलाट हो चुकी है राज्यों को उन की आबादी के अनुसार, बिलकुल स्ट्रिक्टली एकार्डिंग टु पापुलेशन। स्ट्रिक्टनैस जहां नही बरती गयी है वहां से शिकायत है। हम ने यह निर्णय किया था कि हम किसी का एलाटमेंट कम नहीं करेंगे। 425 ग्राम के हिसाब से जोड़ कर जिस राज्य का जो एलाटमेंट है वह उस को देंगे, लेकिन अगर कहीं इस से ज्यादा एलाटमेंट पहले से है तो उस को काटेंगे नहीं, घटायेंगे नही। क्योंकि लोगो को, जिन की एक आदत पड़ चुकी है उस में से अगर काटेंगे तो उस से उन को तकलीफ होती है। दिल्ली में एक किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी वितरण होती रही। हम ने उस में कोई कमी नही की यद्यपि हम को उसे काट कर आधा कर देना चाहिए था, अगर दिल्ली के नागरिकों के साथ वैसा ही व्यवहार करना होता जैसा कि सारे देश के नागरिकों के साथ हो रहा है, लेकिन हम ने दिल्ली के साथ और कुछ छोटे-मोट राज्जों में जैसे मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह, जो थोड़ी चीनी की खपत करते हैं और बार्डर पर होने के नाते उन के साथ कुछ विशेष व्यवहार किया जाता है, उन को छोड़ कर सब के साथ समान व्यवहार करने का और समान रूप से चीनी वितरण करने का इंतजाम किया है।

अब यह कहा गया कि कुछ लोगों को अपने राजनीतिक विश्वासों के अनुसार कुछ

[श्री भानु प्रताप सिंह]

एलर्जी है। हर बात में वह यही देखते हैं कि हमारे पर मिल-मालिकों का दबाव है, हम मिल-मालिकों के प्रलोभन में है। मैं इस का बिल्कुल खंडन करता हूं, अपनी पूरी शक्ति के साथ। इस सरकार पर किसी मिल मालिक का कोई प्रभाव कम से कम चीनी के क्षेत्र में पड़ने वाला नही है और जो भी निर्णय होगा वह चीनी मिल-मालिकों के हित को देख कर नही होगा, केवल किसानों के हित को देख कर होगा, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि किसानों का हित आज इस में है कि वे गन्ने की खेती को कम करें। दूसरी चीजें पैदा करें और यह संभव है कि दूसरी चीजें पैदा कर के उन को उतना मुनाफा हो सकता है जितना कि गन्ने की खेती में उन को है। जैसा कि मैंने कहा है, उस की कीमत बढ़ाये जाने की बात कही जाती है। मैं ने बताया कि उस की न देश में मांग है और न उस की विदेश में मांग है। किसान उस को पैदा कर के क्या करेंगे। इसलिए जिन चीजों की मांग है उसको उन्हें ज्यादा पैदा करना चाहिए। मैंने इस सदन में और दूसरे सदन में भी यह कहा है कि देश में गन्ने की खेती कम की जानी चाहिए। रेडियो पर भी यह कहा है लेकिन यदि किसान इस मेरे मश्विरे को नही स्वीकार करते तो दो ही रास्ते रह जाते है। या तो हम कानून से उन को रोकें और खेती को कम करायें या हम गन्ने के दाम को कम कर दें और उस दशा में खुद ही गन्ने की खेती उन को कम करनी पड़ेगी। मैं तो यह चाहता हूं कि यदि उस की खेती वह स्वयं ही कम कर दें और जिन चीजों की जरूरत है उन को वह पैदा करें तो ज्यादा अच्छा है और इस से यह समस्या हल हो सकती है। और यह कहना कि बगास से यह बनाया जा सकता है या वह बनाया जा सकता है, इस दिशा में वह विचार कर रहे है। दूसरे देशों से सभी सम्पर्क बनाये हुए हैं कि वे किस तरह से करते हैं। लेकिन रिसर्च का काम या फैक्टरी बन जाना यह एक साल में होने वाला नही है। कोई रास्ता निकल आयगा तो हम जरूर कहेंगे कि गन्ने की खेती बढ़ाई जाएगी। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें चीनी का दाम घटा दिया जाए तो उस से समस्या हल नही होगी।

मुझसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मुनाफा कराया गया, एक्साइज रिलीफ दी गई। मेरी कठिनाई यह है कि मैं वे सारे आंकड़े यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं। अगर करूं तो इजलास में पेश किया जाएगा और उसका लाभ फैक्टरी को होगा। मैं सभी माननीय सदस्यो को आमंत्रित करता हूं कि जिनको कोई सन्देह है इस विषय में आकर मुझे से बात करे? मैं उनको आकड़े समझा सकता हूं। कोई भी न तो उनके साथ रियायत की गई है, न जनरोसिटी की गई है बल्कि किसानों के हित में जो कुछ करना उचित था फैक्टरियों को चलाने के लिए केवल उतना ही किया गया है।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Sir, so far as the outside demand or the international demand for sugar is concerned, I want to ask only one question of the hon. Minister. He has said that from £ 700 it has come down to £ 100. I want to know whether this is the position even in relation to superfine sugar. So far as we know, the demand for sugar, particularly superfine sugar, in West Asian countries, namely, Iran and other rich oil producing countries, is very great. Not only is the demand great but they are also prepared to pay a much higher price than prevails in the international market. If that is the position, why is the Government not applying its mind to the diversification of production and producing superfine variety of sugar, and requesting the existing mills—I know it tokes much time to set up new factories—to diversify the production

and produce superfine variety of sugar. I am only asking them to produce superfine variety of sugar for which there is a large demand in West Asian countries. Will this aspect of the matter be considered by the Government?

SHRI SYED SHAHEDULLAH (West Bengal): Sir, an impression was sought to be created that the West Bengal Government have not paid the cane growers. So far as I know, it was a privately run business enterprise and it had to be taken over by the Government as a sick industry. Now, the West Bengal Government have inherited many problems and many problems have been handed over to it by the previous regime. It is difficult to account for all those things in the Rajya Sabha or in Parliament here. If any hon. Member has anything to ask, I think it will be good if he asks the West Bengal Government who can answer the question. This was just a little diversion.

Of course, I endorse the demand that the Government should take over the wholesale trade in sugar and also the sugar mills, excepting the co-operative mills, though I know their character.

श्री टी० अंजैया (आंध्र प्रदेश): उपसभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि शुगर जो किसान पैदा कर रहे है वह कम करनी चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसा कहना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो—जैसे क्युबा है, गुयाना है, आस्ट्रेलिया है जो लोग शुगर या पैट्रोल जैसे जो भी रिसोर्सेज उनके पास है उससे अपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं और शुगर से कई बाई-प्रोडक्ट्स बना कर दूसरे देशो को भेजते हैं। जैसे हर मुल्क के अन्दर कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे पेट्रोल है उसका लाभ उठाने के बजाय यह कहना कि प्रोडक्शन कम किया जाए, यह मिल मालिकों का दबाव है क्योंकि वे चाहते हैं कि ज्यादा प्राइस हो और कम प्राडक्शन हो। जब तक यह सरकार इन कारखानों को नही लेगी, इन का नेशनलाइजेशन नही किया जाएगा तब तक यह समस्या कभी हल नहीं होने वाली है। किसानों को लूटा जा रहा है और इसका फायदा दलाल, एजेंट, कैपिटलिस्ट और कांट्रेक्टर्स उठा रहे है। जब तक यह सरकार कारखानों को नेशनलाइज नही करती तब तक किसानो का मसला हल नही होने वाला है। आप हमेशा यह कहेंगे कि गन्ने की प्रोडक्शन कम करो लेकिन इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आज शुगर के लिए गांवों-गांवों में भागना पडता है लेकिन शुगर नहीं मिलती जब कि चीनी ब्लेक मार्किट में बिकती है। शुगर पार्ट आफ फूड बन गयी है। हर इंसान के लिए, चाय पीने वालों के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब के लिए आवश्यक चीज हो गई है। जबसे प्रोहीबिशन की बात हुई है तब से सारा गुड़ वहां चला जाता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जब तक इनका नेशनलाइजेशन नहीं होगा, तब तक किसानों का भला नही होने वाला है।

श्री भानु प्रताप सिंह: श्रीमन्, अभी सुपर फाइन शुगर की बात कही गई है। मेरे अपने देश में वह बहुत कम बनती है। उसके बाहर भेजने की कोई खास संभावना नही है। हमारे यहां जो शुगर बनती है वह एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत से देश इसे ले जाकर फिर से रिफाइन करते है। अब इसकी आगे क्या संभावना हो सकती है इस पर हम विचार करेंगे। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि सारी मशीनरी इत्यादि को बदलना पड़ता है। जितना आसानी से हो सकेगा और अगर इसकी सचमुच मांग है तो उस पर विचार कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अपने देश में सुपर फाइन शुगर बहुत कम बनती है, सिर्फ पांच हजार टन बनती है।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

वैस्ट बंगाल की भी चर्चा की गई है वह मेरी समझ में नहीं आया है। मैंने वैस्ट बंगाल के बारे में कुछ नहीं कहा है।

यह प्रश्न जो उठा है कि नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण से समस्या हल हो जाएगी, एक तो यह कि मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस दल के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव पारित किया था तत्कालीन शासनारूढ़ दल ने और उनको अपने प्रस्ताव पर अमल करने के लिए काफी लम्बा समय मिला था, मगर उन्होंने नहीं किया। हम नहीं मानते कि राष्ट्रीयकरण से कोई समस्या हल होने वाली है। अपने देश में बहुत सारी फैक्टरियां राष्ट्रीयकृत हो चुकी है, मगर वहां के किसानों को कोई राहत मिली हो या उनको कोई ज्यादा सुविधा मिली हो ऐसी बात नहीं है। हम चीनी मिलों के कोआपरेटिवाइजेशन के पक्ष में जरूर है। आज जितनी चीनी देश में पैदा हो रही है उसकी आधी कोआपरेटिव सैक्टर मे पैदा हो रही है। यद्यपि कोआपरेटिव सैक्टर बहुत देर से शुरू हुआ, लेकिन उसकी चीनी बनाने की मात्रा बढ़ती जा रही है। आधे से ज्यादा चीनी कोआपरेटिव सैक्टर में बन रही है।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Sir, I give a clarification in regard to my suggestion. I thought that the the hon. Minister will give deep consideration to it. It seems—I may be wrong—that he has brushed aside the whole thing. About the machinery parts, I can say that it does not take more than a year to be able to manufacture the necessary machinery. Some industries we have already got In Allahabad, there is Triveni Engineering who are producing sugar mill parts. I only suggested that the mills producing superfine sugar should be asked to diversify production. My information is that there is demand for it and we can get much higher price. As the hon. Minister says, if our superfine sugar is taken by some country, it is refined by them and they get a higher price for it. My only question, my only suggestion and my only request is this. Why not immediate attention be given to the question of diversification of production? So far as the aspect of export is concerned, there is no difficulty. So far as the question of machinery is concerned, much time will not be taken. Now, he referred to the price. Not only now. For sometime to come, the price trend is going to continue and there is no relief. Therefore, this is a very serious matter. Diversification has always been done in such a crisis.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister will certainly consider it. He has said it.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: I would only say that this aspect should receive his consideration. He should immediately start thinking on this. If necessary, the public sector may come in. It is necessary that we should also ask the private as well as the co-operative sectors to diversify and produce as much superfine sugar as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am sure the hon. Minister will consider this suggestion.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मैं इन बातों पर विचार करूंगा, लेकिन जितनी आशा माननीय सदस्य को है उसमें मुझे सन्देह है। लेकिन फिर भी मैं खुले दिमाग से उनकी बातों पर विचार करूंगा।